



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223371
CG-DL-E-27112020-223371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3745]

नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/अग्रहायण 5, 1942

No. 3745]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

का.आ. 4250(अ).—केंद्रीय सरकार, स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या उनमें से इतने प्रतिशत को जो आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट है ऐसी जूट पैकेजिंग सामग्री में उसके आपूर्ति या वितरण किए जाने के प्रयोजन से पैक किए जाने के लिए सशक्त है;

और केंद्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जूट सामग्री में पैकेजिंग के मानकों की सिफारिश करने के लिए संख्यांक का.आ. 473(अ), तारीख 27 जनवरी, 2019 द्वारा स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया है;

और केंद्रीय सरकार, स्थायी सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् इस बात से संतुष्ट है कि जूट पैकिंग सामग्री में पैक किए जाने के लिए वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या उसके प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना, कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और इनके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में अनिवार्य है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संख्यांक का.आ. 4578 (अ), तारीख 20 दिसंबर, 2019 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण

से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे न्यूनतम प्रतिशत में आपूर्ति और वितरण के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 2021 तक जूट पैकेजिंग सामग्री में पैक की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी.

क्रम संख्यांक	वस्तुएं	भारत में उत्पादित कच्चे जूट से भारत में विनिर्मित जूट पैकेजिंग सामग्री में पैक करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग के कुल उत्पादन का न्यूनतम प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
(i)	खाद्यान्न	"उत्पादन का शत प्रतिशत (100 %)
(ii)	चीनी	"उत्पादन का बीस प्रतिशत (20 %)

* **टिप्पण 1:-** आरम्भ में खाद्यान्न के लिए मांग पत्र का दस प्रतिशत प्रतिवर्ती नीलामी के माध्यम से सरकारी ई-विपणन पोर्टल (जीईएम) पर रखा जायेगा।

** **टिप्पण 2:-** उपापन एजेंसियों द्वारा मिलों या खुले बाजार से सीधा क्रय के अधीन विविध प्रकार के जूट थैले।

2. सरकारी ई-विपणन (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए जूट थैलों का उपापन परीक्षण आधार पर आरम्भ किया जायेगा।

3. शुरुआत में, मांग पत्र का दस प्रतिशत राज्य उपापन एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ती नीलामी के माध्यम से सरकारी ई-विपणन (जीईएम) पोर्टल पर रखा जायेगा।

4. उस विस्तार तक जहाँ तक जूट मिलें सरकारी ई-विपणन (जी ई एम) पोर्टल बोली के माध्यम से अनुज्ञात तीस दिन के भीतर आपूर्ति करने में असफल रहती हैं, वस्त्र मंत्रालय आज्ञापक पैकेजिंग मानक का अग्रिम क्षीणीकरण अनुज्ञात करेगा।

5. जूट पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति किसी कमी या बाधा की दशा में या अन्य आकस्मिक या अत्यावश्यक दशा में, वस्त्र मंत्रालय सम्बंधित उपयोक्ता मंत्रालयों के परामर्श से उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट पैकेजिंग सामग्री का अधिकतम तीस प्रतिशत तक और क्षीणीकरण अनुज्ञात कर सकेगा।

6. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तैयार आपूर्ति योजना के अनुसार उपापन एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न पैक के लिए जूट थैलों का मांग पत्र नहीं रखने की दशा में और मांगो का समूह (मांग पत्र) उत्पन्न होता है, तब जूट मिलों को जूट थैलों के आपूर्ति के लिए युक्तियुक्त अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

7. उच्च सघनता का पॉली एथिलीन/पॉली प्रोपीलीन (एचडीपीई/पीपी) थैले के न्यूनतम प्रयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्य उपापन एजेंसियों (एफसीआई सहित) के परामर्श और समन्वय से जूट थैलों की पूर्ति के पूर्व-सहमति अनुसूची के अनुसार समय पर वास्तविक मांगपत्रों को रखा जाएगा :

परंतु यदि विस्तारित अवधि में थैलें का आपूर्ति करने में मिलें असफल रहती हैं तो क्षीणीकरण से संबंधित शर्तें लागू होंगी।

8. उक्त अधिनियम के अधीन आरक्षित की परिधि से निम्नलिखित को बाहर रखा जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) विटामिन से पुष्ट चीनी;

(ख) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पैकेजिंग ;

(ग) खाद्यान्नों के लिए दस कि.ग्रा. और उससे कम और चीनी के लिए पच्चीस कि.ग्रा. और उससे कम के छोटे उपभोक्ता पैकेज;

(घ) सौ कि.ग्रा. से अधिक थोक पैकेजिंग; और

(ङ.) निर्यात के लिए पैक की गई चीनी जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किए गए निर्धारण और सिफारिशों के आधार पर निर्यात नहीं की जा सकी थी।

9. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कच्चे जूट और जूट पैकिंग सामग्री के उत्पादन में लगे व्यक्ति आज्ञापक पैकिंग से लाभ प्राप्त करें, जूट श्रमिकों को कानूनी शोध और जूट किसानों को तथा कच्चे जूट के उपापन पर गाँठ बनाने वालों को त्वरित भुगतान के लिए समर्थ बनाने के लिए वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) सहित प्रवृत्त श्रमिक विधियों के अनुसार उचित क्रियाविधि बनाई जाएगी।

[फा. सं. जे-7/3/2020-जूट (भाग 1)]

संजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 26th November, 2020

S.O. 4250 (E).—Whereas, the Central Government is empowered under sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) to specify, by order, the commodities or class of commodities or such percentage thereof to be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material, after considering the recommendations of the Standing Advisory Committee;

And whereas, the Central Government has, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the said Act, constituted the Standing Advisory Committee *vide* number S.O. 473(E), dated the 27th January, 2019, to recommend the norms of packaging in jute material;

And whereas, the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary in the interest of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof, to specify the commodity or class of commodities and percentage thereof to be packed in jute packaging material;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1) of section 16 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), and in supersession of order number S.O. 4578(E), dated the 20th December, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Table below, shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, upto the 30th June, 2021, namely:-

TABLE

Serial Number	Commodities	Minimum percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India
(1)	(2)	(3)
(i)	Foodgrains	*Hundred per cent. (100%) of the production
(ii)	Sugar	**Twenty per cent. (20%) of the production

***Note1:-** Initially ten per cent. of the indents for foodgrains would be placed through reverse auction on the Government e-Marketplace (GeM) portal.

****Note 2:-** In diversified jute bags under direct purchase by the procuring agencies from the mills or open market.

2. Procurement of jute bags for packing of foodgrains through the Government e-Marketplace (GeM) portal shall be initiated on trial basis.

3. To begin with, ten per cent. of the indents shall be placed by the State Procurement Agencies through reverse auction on the Government e-Marketplace (GeM) portal.

4. To the extent jute mills fail to supply through the Government e-Marketplace (GeM) portal bidding within the permissible thirty days, the Ministry of Textiles will allow upfront dilution of mandatory packaging norm.

5. In case of any shortage or disruption in supply of jute packaging material or in case of any other contingency or exigency, the Ministry of Textiles may, in consultation with the user Ministries concerned, allow further dilution of packaging material up to a maximum of thirty per cent. of the percentage specified in column (3) of the said Table.

6. In case the Procurement Agencies do not place indents for jute bags to pack foodgrains as per supply plan prepared by the Department of Food and Public Distribution and bunching of demand (indents) takes place, then the jute mills shall get reasonable additional time for the supply of jute bags.

7. With a view to ensure the minimum usage of High Density Poly Ethylene/ Poly Propylene (HDPE/PP) bags, the Department of Food and Public Distribution, in consultation and coordination with State Procurement Agencies (including FCI) shall place realistic indents on time as per pre-agreed schedule of supply of jute bags:

Provided that if the mills fail to supply the bags in the extended period, the conditions relating to dilution shall be applicable.

8. The following may be kept out of the purview of reservation under the said Act, namely :-

- (a) sugar fortified with vitamins;
- (b) packaging for export of commodities;
- (c) small consumer packs of ten kilograms and below for foodgrains and twenty-five kilograms and below for sugar;
- (d) bulk packaging of more than one hundred kilograms; and
- (e) sugar packed for export but which could not be exported on the basis of an assessment and recommendation by the Department of Food and Public Distribution.

9. To ensure that persons engaged in production of raw jute and jute packaging material are benefitted from the mandatory packaging, a suitable mechanism shall be devised for enabling payment of statutory dues to jute workers and prompt payment to jute farmers and balers on procurement of raw jute as per the Labour Laws in force including the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).

[F. No.J-7/3/2020-Jute (Part.I)]

SANJAY SHARAN, Jt. Secy,